

# नीट-यूजी और सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी-यूजी में गड़बड़ी

**एक और परेशानी** ▶ देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा तकनीकी खामी का शिकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नीट-यूजी के पेपर लीक व सीबीएसई के आन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) के जरिये कराए गए मूल्यांकन में गड़बड़ियों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि शनिवार को विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी और नीट-यूजी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी की गड़बड़ियों का एक नया मामला सामने आया। एनटीए के अंदर खामी किस तरह व्याप्त हैं, इसका नजारा फिर देखने को मिला। सीयूईटी-यूजी की शनिवार सुबह नौ बजे से होने वाली परीक्षा तकनीकी गड़बड़ियों के चलते समय पर शुरू नहीं हो पाई। बाद में लंबी मशक्कत के बाद परीक्षा को दो से ढाई घंटे की देरी से कराया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर भारी अफरा-तफरी का माहौल रहा।

इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने तकनीकी गड़बड़ियों के चलते परीक्षा समय से शुरू न हो पाने को लेकर अभिभावकों व छात्रों से खेद

▶ पहली पाली की परीक्षा दो घंटे देरी से शुरू हुई, दूसरी पाली का पेपर भी एक घंटा लेट, परेशान दिखे छात्र-अभिभावक

▶ एनटीए ने जताया खेद, कहा- बायोमीट्रिक के बाद भी जो 3,765 छात्र नहीं दे पाए परीक्षा, उन्हें मिलेगा एक और मौका



नई दिल्ली के सरिता विहार स्थित एक परीक्षा केंद्र पर शनिवार को छात्र सीयूईटी-यूजी 2026 में शामिल होने के लिए पहुंचे।

एएनआइ

जताया है। एनटीए के मुताबिक 30 मई को 73,106 छात्र परीक्षा के लिए केंद्रों पर पहुंचे थे और इन्होंने अपना बायोमीट्रिक रजिस्ट्रेशन भी पूरा किया। इनमें से 69,341 छात्र यानी करीब 95

प्रतिशत ने अपनी सुबह पाली की परीक्षा को पूरा किया है। तकनीकी दिक्कतों के चलते परीक्षा में हो रही देरी का 3,765 छात्रों ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और चले गए। पहली पाली के इन छात्रों को

**राहुल गांधी ने उठाए सवाल, कहा- एक भी परीक्षा ईमानदारी से नहीं**

सीयूईटी-यूजी में गड़बड़ी सामने आने के बाद कांग्रेस नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। कहा- नीट, सीबीएसई और एसएससी के बाद अब सीयूईटी में भी गड़बड़ी हुई है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा- 'चार परीक्षाएं। एक करोड़ बच्चे। एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्वगुरु के मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी।'

परीक्षा का एक और मौका दिया जाएगा। परीक्षा की तारीख जल्द घोषित होगी।

परीक्षा में देरी की जानकारी छात्रों को मैसेज से दी गई

पेज>>5

# भ्रष्टाचार पर सरकार का प्रहार • ईडी के दस्तावेजों-साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई रिशुश्री के कमीशन मॉडल में फंसे... दो आईएएस योगेश व अभिलाषा सस्पेंड



पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

बिहार की नौकरशाही में बैठे भ्रष्टाचार के नेटवर्क पर वड़ा वार करते हुए सम्राट सरकार ने दो आईएएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। 2014 बैच की आईएएस अफसर अभिलाषा कुमारी शर्मा और 2017 बैच के योगेश कुमार सागर पर आरोप है कि इन्होंने ठेकेदार रिशुश्री के जरिए रिश्वत, कमीशन और पर्सनल फायदे का पूरा सिंडिकेट खड़ा कर रखा था। सामान्य प्रशासन विभाग ने यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा जुटाए गए दस्तावेजों, सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर की है। रिशुश्री को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

जांच में सामने आया है कि यह सिर्फ रिश्वत का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था, जिसमें सरकारी फैसलों के बदले ठेकेदार से मोटी रकम वसूली जाती थी। ईडी के दस्तावेज, डिजिटल ट्रेल और गवाहों के बयान इस पूरे खेल की पुष्टि करते हैं। अभिलाषा शर्मा फिलहाल जीविका सोसाइटी में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और योगेश कुमार सागर समाज कल्याण निदेशक थे। दोनों के खिलाफ अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के तहत यह कार्रवाई की गई है। दोनों निलंबन अवधि में सामान्य प्रशासन विभाग में हाजिरी देंगे। दोनों का वेतन बंद रहेगा। केवल जीवन निर्वाह के लिए भत्ता मिलेगा। -शेष पेज-13

## 70 दिनों में कंपनी से बैन हटा... विदेश यात्रा पर गए योगेश

शशि सागर • पटना | बिहार के प्रशासनिक गलियारों में भ्रष्टाचार का ऐसा 'इकोसिस्टम' चल रहा था, जहां ठेके के बदले आईएएस को विदेश की सैर कराई जाती थी। ईडी की जांच में बुडको के तत्कालीन एमडी योगेश कुमार सागर और जीविका की तत्कालीन अतिरिक्त सीईओ अभिलाषा शर्मा के नाम सबसे ऊपर हैं। गुजरगत की कंपनी 'जैन एंजीकोन' को बुडको ने 7 मार्च 2024 को प्रतिबंधित किया था। लेकिन रिशुश्री के प्रभाव से महज 70 दिन में ही 16 मई 2024 को प्रतिबंध हटा लिया गया। इसके

तुरंत बाद जून के अंतिम हफ्ते में आईएएस योगेश परिवार के साथ ऑस्ट्रिया की सैर पर निकल गए। यात्रा का 21.92 लाख का खर्च रिशुश्री और इसी कंपनी ने उठाया था। यही नहीं, योगेश सागर ने एमडी रहते हुए इसी कंपनी को छपरा में ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम भी थमा दिया। 12 जून 2025 को जब ईडी ट्रेवल एजेंट अतुल के चहछे छापेमारी कर रही थी, तब नीलेश पटेल नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने एजेंट को चेतावनी दी कि ईडी को योगेश और उनकी यात्राओं के बारे में कुछ न बताया जाए।

### ईडी का बुराबान • रिशुश्री के कंटेनर में ये जकरार... एकोन रिपोर्ट में ईडी कुंजी कमीशन का रिशुश्री मॉडल...3.5% में फाइल पास, 7% में टेंडर फिक्स

रिशुश्री का बुराबान • रिशुश्री के कंटेनर में ये जकरार... एकोन रिपोर्ट में ईडी कुंजी  
कमीशन का रिशुश्री मॉडल...3.5% में फाइल पास, 7% में टेंडर फिक्स  
रिशुश्री का बुराबान • रिशुश्री के कंटेनर में ये जकरार... एकोन रिपोर्ट में ईडी कुंजी  
कमीशन का रिशुश्री मॉडल...3.5% में फाइल पास, 7% में टेंडर फिक्स

29 मई को प्रकाशित खबर

### आईएएस अभिलाषा शर्मा की यात्राओं और पूजा-पाठ पर भी 29 लाख खर्च

भ्रष्टाचार की यह जड़ें कितनी गहरी थीं, इसका अंदाजा आईएएस अभिलाषा कुमारी शर्मा के केस से लगता है। रिशुश्री ने उनके कहने पर पंडित इंद्रजीत शर्मा को पूजा-पाठ के लिए 9.84 लाख रुपए का भुगतान किया था। इसके अलावा अभिलाषा की यात्राओं पर 19 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें से उनके पति ने मात्र 6 लाख ही दिए थे। रिशुश्री ने उन्हें महंगे मॉट ब्लैक पेन, एप्पल आईपैड और आईफोन भी गिफ्ट किए थे। हालांकि, रिशुश्री ने कोर्ट में इसे 'राखी का उपहार' बताकर बचने की कोशिश की।

### बिहार के कई आईएएस अधिकारियों के नाम ईडी की रिपोर्ट में, जांच तेज

ईडी की रिपोर्ट में कई आईएएस और अन्य अधिकारियों के रिशुश्री से करीबी संबंधों की चर्चा है। रिपोर्ट कहती है कि इसी संबंधों के बदौलत रिशुश्री ने बिहार के सरकारी ठेकों में करप्ट इकोसिस्टम तैयार कर लिया था। आईएएस अधिकारी योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा के अलावा संजीव हंस, धर्मेन्द्र कुमार, आनंद किशोर, संतोष कुमार मल्ल, सुनील कुमार यादव और अमरेंद्र कुमार से संबंधों की विस्तार से चर्चा है। इसके अलावा सहरसा के तात्कालीन नगर आयुक्त मुमुक्षु चौधरी, चीफ इंजीनियर तारणी दास व अन्य का नाम भी रिपोर्ट में है।

## आईएएस अफसरों की विदेश यात्रा का सच

Q आईएएस योगेश सागर की ऑस्ट्रिया यात्रा का भुगतान कैसे हुआ?

A यात्रा का कुल खर्च 21,92,500 रुपये था। इसमें से मात्र 4.27 लाख रुपये योगेश सागर की पत्नी (अवलोकिता अशोक) के बैंक खाते से दिए गए। बाकी 17.65 लाख रुपये रिशुश्री के सहयोगियों ने हवाला नेटवर्क के जरिए चुकाए।

Q क्या विदेश यात्रा के विलों में कोई हेराफेरी भी की गई थी?

A हां, भारी हेराफेरी हुई। महंगे होटलों के बिल छिपाने के लिए बुकिंग रिश्तेदारों के नाम पर की गई। योगेश सागर के कहने पर बिल में ठहरने की तारीखें भी बदली गईं, ताकि वे इसे अपनी पत्नी के दफ्तर में यात्रा के सबूत के तौर पर दिखा सकें।

Q रिशुश्री अधिकारियों की मदद कैसे-कैसे करता था?

A रिशुश्री अधिकारियों के होटल, फ्लाइट टिकट और पर्सनल खर्च उठाता था। बदले में ये अधिकारी उसकी कंपनियों को बिहार में बड़े ठेके दिलवाते थे। रिशुश्री के पास अधिकारियों की हर यात्रा और रुकने की जानकारी पहले से होती थी।

संडे एंकर

# 15 साल से 65 साल तक की उम्र वाले 16.5 प्रतिशत पुरुष कर रहे शराब का सेवन एनएफएचएस-6 की रिपोर्ट ने खोली पोल.... शहरों से अधिक गांव में शराब पीने वाले बढ़े; निजी अस्पतालों में 'सिजेरियन' की लूट हो रही

भास्कर न्यूज | पटना

बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दावा कागजों पर भले ही मजबूत हो, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। 29 मई को जारी राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे-6 (एनएफएचएस-6) की रिपोर्ट ने राज्य के सामाजिक और स्वास्थ्य ढांचे की पोल खोल कर रख दी है। रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि बिहार में पाबंदी के बावजूद शराब पीने वालों की तादाद घटने के बजाय बढ़ गई है। अब राज्य में 15 से 65 साल की उम्र के 16.5 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन कर रहे हैं, जबकि पिछले सर्वे (एनएफएचएस-5) में यह आंकड़ा 15.4 प्रतिशत था। यानी

घर की चहारदीवारी में बढ़ी हिंसा, रूह कंपा रहे आंकड़े

शराब के बढ़ते चलन का सीधा असर बिहार की 'आधी आबादी' पर पड़ रहा है। राज्य में जेंडर आधारित हिंसा में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 18 से 29 साल की युवतियां सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार हो रही हैं। विडंबना यह है कि गांवों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों की महिलाएं (2.1%) इस हिंसा की ज्यादा शिकार हैं। सबसे दर्दनाक तथ्य यह है कि 18 से 49 वर्ष की 5.4 प्रतिशत विवाहित महिलाएं अपनी गर्भावस्था के दौरान भी हिंसा का शिकार हुई हैं। ऐपवा की राष्ट्रीय महासचिव मीना तिवारी का कहना है कि बिना प्रशासनिक मिलोभगत के शराब गांवों तक नहीं पहुंच सकती।

कानूनन सख्ती के बाद भी पीने वालों की संख्या में 1.1 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट का सबसे काला पहलू यह है कि शराब का नशा शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पैर पसार चुका है। गांवों में

15 वर्ष से ऊपर के 17.1 प्रतिशत पुरुष शराब पी रहे हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 12.8 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की आसान पहुंच, स्थानीय स्तर पर बनने वाली 'चुलाई' और पुलिसिया निगरानी की कमी को

इसकी मुख्य वजह माना जा रहा है। प्रशासन के तमाम दावों के बीच गांवों में शराब की यह उपलब्धता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर बिहार ने संस्थागत प्रसव (अस्पतालों में जन्म) में सुधार किया है, जो 76.2% से बढ़कर 81.1% हो गया है। लेकिन यहां भी एक बड़ा 'खेल' उजागर हुआ है। राज्य में सिजेरियन डिलीवरी (ऑपरेशन) की दर 13.2% तक पहुंच गई है। सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव मात्र 2.7% हैं, जबकि निजी अस्पतालों में आंकड़ा डराने वाला है। प्राइवेट अस्पतालों में 49.3 प्रतिशत प्रसव ऑपरेशन के जरिए हो रहे हैं। यानी निजी सेंटर्स में होने वाली हर दूसरी डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है।



भास्कर इनसाइट

कागजी सख्ती व जमीनी मिलीभगत का नतीजा

बिहार में शराबबंदी के बावजूद पीने वालों की संख्या बढ़ना साफ करता है कि सिस्टम में कहीं बड़ा छेद है। ग्रामीण इलाकों में निगरानी की कमी और तस्करी के नेटवर्क ने शराबबंदी को मजाक बना दिया है। वहीं, निजी अस्पतालों में बढ़ते सिजेरियन केस बताते हैं कि स्वास्थ्य सेवा अब सेवा कम और मुनाफाखोरी का जरिया ज्यादा बन गई है। सरकारी नियंत्रण के बिना ये आंकड़े भविष्य में और भी भयावह हो सकते हैं।

# Shivakumar will take oath as Karnataka CM on June 3

Governor invites current deputy Chief Minister to take oath after he was unanimously elected leader of the CLP; speculation remains over Cabinet and whether there will be new deputy CMs

**Sharath S. Srivatsa**  
BENGALURU

**K**arnataka Pradesh Congress Committee president D.K. Shivakumar will take oath as the Chief Minister at the Lok Bhavan on Wednesday after being unanimously elected the leader of the Congress Legislature Party (CLP) on Saturday.

Governor Thaawarchand Gehlot, in a communique to Mr. Shivakumar, has invited him to take the oath at 4.05 p.m. on Wednesday. It is expected to be a simple event at the Glass House on the Governor's residential premises. The event is expected to be attended by the central leadership of the party.

The invitation came after a delegation of Congress leaders, including Mr. Shivakumar and caretaker Chief Minister Siddaramaiah, met the Governor to hand over the CLP resolution on the election



**New role:** Karnataka CM-designate D.K. Shivakumar with supporters after the CLP meeting in Bengaluru on Saturday. K. MURALI KUMAR

of a new leader. The letter said 135 Congress legislators, two associate members, and one Raitha Sangha member had unanimously elected Mr. Shivakumar as the CLP leader. Earlier in the day, Mr. Shivakumar had met the Governor informally to check his availability for the dates chosen for swearing in. With Cabinet forma-

tion still under discussion, speculation continues over whether a full Cabinet will be sworn in and whether there will be deputy Chief Ministers.

"The Congress high command proposed the name of Mr. Shivakumar for the post of CLP, and he was unanimously elected. The power transition took place under the guidance

of Congress president Mallikarjun Kharge, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and leader Sonia Gandhi," Congress general secretary (organisation) K.C. Venugopal told presspersons. "With the support of Mr. Siddaramaiah and under the leadership of Mr. Shivakumar, the Congress will return to power in 2028," he said.

Addressing speculations surrounding the power transition, Mr. Venugopal said, "Several people had predicted that the Congress would be in trouble during the power transition. Everyone speculated about the move of Mr. Siddaramaiah. However, by his decision, he has shown that he only has the Congress party in his heart. It proves that Congress is one family."

**CONTINUED ON**

» PAGE 8

**'ROCK' OF CONGRESS**

» PAGE 14

# NFHS-6 records rise in obesity and C-section births in southern States

Andhra Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu record high rates of overweight and obese adults, alongside a rising prevalence of diabetes; the latest survey also notes a high rate of Caesarean births, accounting for 27.2% of deliveries nationwide

**Bindu Shajan Perappadan**  
NEW DELHI

The latest National Family Health Survey (NFHS-6) has highlighted the rapid rise in obesity and diabetes across India. Obesity in women (15-49 years) has gone up from 24% in the NFHS-5 to 30.7% in the latest NFHS-6, and similarly obesity in men of the same age group from 22.9% to 27.3%.

Diabetes among persons taking medicines to control insulin resistance has risen from 13.5% to 17.8% in women, and 15.6% to 20.9% in men.

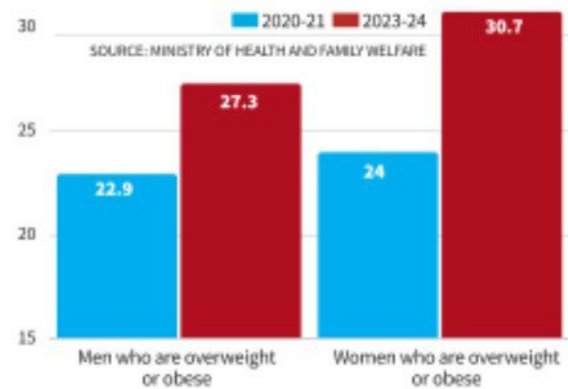
## Obesity prevalence

The survey has indicated that obesity/overweight prevalence has increased by about 6.7% among women and 4.4% among men in just five years.

This is particularly so in the southern States of Andhra Pradesh, Kerala, and Tamil Nadu, which have emerged as a hotspot for

## Sizing up national health

The chart shows rising obesity in men and women (aged 15 to 49) between 2021 and 2024 (in %)



overweight and obese adults, alongside rising diabetes prevalence.

The survey also records an exceptionally high rate of Caesarean (C)-section births, with Telangana at 62.2%, Andhra Pradesh at 52.2%, and Tamil Nadu at 46.9%.

## Rise in C-section births

The national share of births by C-section stood at

27.2%, up from 21.5% recorded in the previous survey. Private hospitals registered 54.1% Caesarean births whereas public hospitals registered 16.9%.

Urban areas reported particularly high rates of C-section deliveries, with around 40.5% of births by C-section when compared with the 22.8% births by C-section in rural areas.

C-sections, obesity, and

diabetes are a two-way street, experts say.

Maternal obesity and diabetes increase risk during pregnancy, resulting in a C-section, and being born via C-section increases a child's long-term risk of developing these metabolic conditions.

The Ministry of Health and Family Welfare released the NFHS-6 earlier this week. It was conducted in 2023-24 by the Ministry along with the International Institute for Population Sciences, Mumbai as the nodal agency.

## 6.79 lakh households

Covering nearly 6.79 lakh households across 715 districts, the survey provides vital evidence on population, health, nutrition, and family welfare indicators, and supports evidence-based planning and programme implementation up to the district-level.

Obesity and diabetes are among the most important global public health challenges because they

substantially increase the risk of illness, disability, and premature death, according to the World Health Organization (WHO).

The global health body defines overweight and obesity as abnormal or excessive fat accumulation that may impair health.

## Risk of Type 2 diabetes

The WHO emphasises that excess body weight is one of the strongest risk factors for developing Type 2 diabetes.

"When people accumulate excess body fat – especially around the abdomen – the body's cells can become resistant to insulin. This condition, called insulin resistance, makes it harder to regulate blood sugar and can eventually lead to Type 2 diabetes," the WHO has said.

The condition results in reduced life expectancy, more years lived with disability, higher risk of multiple chronic diseases, and increased healthcare costs.

# Why is CBSE's evaluation system facing flak?

What is the On-Screen Marking system and why is it under scrutiny? What is its history? Has it been successful elsewhere? Why did CBSE introduce it and how did it pan out? How has the Board responded to the crisis?

G. Sampath

## The story so far:

Following the release of the Class 12 Board exam results, the Central Board of Secondary Education (CBSE) has been under fire for discrepancies in the evaluation of answer scripts and malfunctioning of the re-evaluation process. The newly introduced On-Screen Marking (OSM) system is under scrutiny, given the widespread sense among students that the marks they received did not match their expectations. The CBSE's pass percentage has dipped to 85.29% this year from 88.39% last year, with the number of students scoring above 90% also dropping.

Due to the sheer volume of requests for answer book copies, the post-results verification portal crashed. As for students who did manage to obtain scanned copies of their answer books, they got a shock when they discovered blurred or missing pages, and unmarked answers. Many even received answer books of other students. The Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth, and Sports has summoned senior officials from the Union Education Ministry and CBSE Chairman Rahul Singh for a meeting on June 2 to review the use of OSM and the problems faced by the students.

## What is On-Screen Marking?

It is a form of digital evaluation of exam answer sheets. Hand-written answer books are digitally scanned, anonymised, and uploaded online. Instead of checking paper copies with a pen, teachers log into a dedicated platform to access the scanned answer books and correct papers on a computer screen, under video surveillance.

## What is the history of OSM in India?

The CBSE tried out OSM on a smaller scale in 2013-14. Due to inadequate digital infrastructure

and limited digital literacy, the experiment was not a big success. Then it proposed testing the OSM in 2024-25 on "small-volume subjects" where there would be fewer candidates. The idea was to sort out glitches before scaling up. In June 2025, members of the CBSE's governing body suggested that OSM "may be implemented in all subjects only after completion of pilot projects in some subjects across various regional offices of the board." But the CBSE ignored the advice of its own governing body. Without adequate pilot testing, it went in for full-scale adoption of OSM across all subjects in 2026.

Amid the ballooning crisis, the CBSE extended the deadline for requesting scanned copies, and also kept revising the fees for these services

## Were teachers able to familiarise themselves with OSM before it was rolled out?

The first Class 12 Board exam was on February 17, but teachers were informed of OSM implementation barely 10 days earlier. This was a time when teachers were busy with exams in schools, and many had duties as Booth Level Officers as well. Many did not get enough time to familiarise themselves with the user interface of the portal, and learn how to scroll, how to mark, and how to go back and recheck if they had missed something. As a result, many did not have enough practice by the time they came to the evaluation centres for the OSM.

## What was the CBSE's rationale for switching from physical marking to OSM?

In a circular dated February 9, the CBSE listed several benefits of moving to OSM. These included elimination of totalling errors, reduced manual intervention, faster evaluation, elimination of the need for post-result verification of marks, and reduced manpower requirements for verification. But these benefits did not materialise. Class 12 exams were given by 17 lakh students. This meant that 98 lakh answer books, or 40 crore pages, had to be manually scanned in record time. These also had to be checked for legibility before being made available for evaluation. The benefit of reduced manual intervention did not appear to have materialised. Nor is there evidence that OSM reduced totalling errors or accelerated evaluation. Contrary to CBSE's claims, requests for "post-result verification" have shot up compared to previous years.

## Has OSM been used successfully elsewhere? If yes, why did CBSE struggle?

Yes, it has been used successfully by exam boards such as Cambridge (U.K.) and International Baccalaureate (IB) and in countries such as Singapore and Australia. But these have far fewer exam centres and students, and more centralised scanning infrastructure, than CBSE. OSM has been known to work well in an ecosystem of well-resourced, digitally ready private schools, such as those under Cambridge and IB. In contrast, CBSE's 33,000 affiliated

schools include government, rural, and semi-urban schools with uneven digital infrastructure and teacher training.

## What is the controversy with the firm contracted to deliver OSM for CBSE?

Opposition leader Rahul Gandhi has alleged corruption in CBSE's selection of COEMPT Eduteck as the OSM vendor and demanded a judicial inquiry. In a video statement, he said, "The company that did the OSM for your exams was actually called Globarena. And Globarena has carried out this scam twice in Telengana... [in 2019 and 2023]." He claimed that though this company's track record was known, for "some hidden" reason, the CBSE chose it for the assignment. The CBSE has claimed that COEMPT was chosen "in accordance with the procurement policy" of the government.

## What was Sarthak Sidhant's viral blog on CBSE about?

A Class 12 student, Sarthak Sidhant, published an investigative blog post which appeared to show that COEMPT Eduteck was the beneficiary of a rigged tendering process. After poring over CBSE's tenders and multiple Request for Proposals, he claimed to have found that the "CBSE did not just pick a bad software vendor by accident. They lowered financial baselines. They dropped software security certifications. They cut the corrupt practices cooling-off period in half. They removed the physical server isolation requirement. They erased the word 'blacklisting' from their penalty matrix via a last-minute corrigendum, before bidding, and they bypassed their own mandatory CERT-In production audits. They gambled with our data security, our marks, and our mental health."

## What were the problems with the re-evaluation portal?

CBSE's portal for obtaining copies of answer sheets went live on May 19. As more than 4 lakh students requested scanned copies of answer sheets, the portal crashed, forcing CBSE to put the site under maintenance.

## How did the CBSE respond?

Amid the ballooning crisis, the CBSE extended the deadline for requesting scanned copies, and also kept revising the fees for these services, leading to confusion among parents and students. Following a public uproar, it began responding individually on social media to affected students. It roped in experts from the Indian Institutes of Technology, Madras and Kanpur to resolve the technical challenges, and has announced that the designated portal for verification and re-evaluation will now go live from June 1 to "ensure a transparent and glitch-free process." Meanwhile, it has also launched a public relations campaign by circulating a social media messaging kit to school principals, directing them to post reels defending OSM and CBSE. These included a statement describing CBSE as "highly proactive, empathetic, and communicative regarding these teething issues."



NSUI activists raise slogans during a protest, alleging irregularities in the CBSE's On-Screen Marking evaluation system, in New Delhi. PTI

# Why is India pushing for coal gasification?

What is coal gasification and how does it have the potential to substitute imports? What technical challenges does high-ash Indian coal pose for gasification? Where does India stand with respect to coal gasification and related technology?

Saptaparno Ghosh

## The story so far:

In a roadshow promoting surface coal gasification, Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy said the technology, which can also yield a range of downstream products, has the potential to substitute imports worth up to ₹3 lakh crore. To encourage coal gasification, the Union Cabinet approved a ₹37,500-crore incentive package.

## What is coal gasification?

Coal gasification entails the conversion of coal into synthetic gas, or syngas, which can be further used to produce downstream products such as urea, methanol, ammonium nitrate, synthetic natural gas (SNG), hydrogen, ether, and dimethyl, among others.

According to government data, India possesses approximately 401 billion tonnes of coal and about 47 billion tonnes of lignite. The rationale behind coal gasification is greater utilisation of these resources besides putting in place a sustainable mining method to produce the downstream products. This, the government believes, will reduce import dependence.



File photo shows coal being loaded onto trucks in Piparwar, about 70 km from Ranchi in Jharkhand. PTI

The high-ash content of Indian coal also differentiates the gasification technology that could be employed in India from that in other countries such as China, Australia, or the U.S.

According to the Union Coal Ministry, India imports one-fifth of its urea requirement, almost its entire ammonia requirement, and approximately 80-90% of its methanol requirement.

The Ministry has set itself a target of gasifying 100 million tonnes of coal by 2030. With the recently announced scheme in place, the government aims to support the gasification of about 75 million tonnes of coal and/or lignite to reach its 2030 target.

## Where does India stand with coal gasification at present?

Before the ₹37,500-crore package was announced this year, the government had approved an ₹8,500 crore package in January 2024. Of this, ₹6,233 crore has been disbursed to eight projects owned by private sector and public-sector undertakings. These include projects being executed through separate joint ventures of Coal India with Bharat Heavy Electricals and Gas Authority of India Ltd, and as well as Coal India's own project in Western Coalfields. Private-sector participants include companies such as Jindal Steel and Greta Energy and Metal.

The Talcher Coal-based Ammonia-urea complex is expected to be commissioned in FY2027-28. The others that include conversion of coal to syngas, ammonium nitrate, direct reduced iron, ethanol, and hydrogen are expected to be commissioned in FY2029-30. In April this year, in response to a query from *The Hindu*, the Ministry had stated that "in the coming months, more projects are expected to be sanctioned".

## Where does India stand with respect to the technology for coal gasification?

Large-scale commercial deployment of gasification in India hinges on navigating issues such as the high ash content of coal, variability in its gross calorific value, and the presence of complex mineral matter, all of which can

impede the gasification process. This is why fluidised-bed gasification is considered particularly suitable for Indian coal. The technology utilises a gas stream that lifts the coal out of ash, thereafter gasifying it with heat.

The high-ash content of Indian coal also differentiates the gasification technology that could be employed in India from that in other countries such as China, which is the world leader in gasification, Australia, or the U.S.

Another aspect relates to the adequate presence of indigenous technology. By their very nature, coal gasification projects are highly capital-intensive and involve long gestation periods. According to independent research by the Chintan Research Foundation (published March 2026), "Recent techno-economic assessments of circulating fluidised bed gasifiers in the Indian context indicate that capital costs constitute the largest share of syngas production costs, accounting for nearly 30% of the total production costs." Thus, financial viability becomes particularly imperative. It is for this reason that the latest package, which provides financial incentives amounting to one-fifth of plant and machinery costs, is essential.

For perspective, state-owned Bharat Heavy Electricals Ltd has developed their pressured fluidised bed gasifier technology tailored specifically to handle the high ash content and variability of Indian coal. Additionally, according to Niti Aayog, its 16 facilities are capable of producing all the critical components required for gasification. In the private sector, Jindal Steel Ltd and Greta Energy and Metal have been able to indigenise about 80-90% of their production. Naveen Ahlawat, Head of Sustainability and Decarbonisation at Jindal Steel, said: "It (indigenising technology) will save costs; your project cost will come down by 30-40%."

At its maturing stages, coal gasification may still require technological imports. It for this reason that industry has also sought the government's consideration of exemptions from provisions of the Department for Promotion of Industry and Internal Trade for acquiring necessary technologies, especially from China. Officials said that the Ministry would support participants in securing clearances for technology imports, though the regulatory requirement will continue.